

प्रेषक,

राधिका झा,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
हल्द्वानी, नैनीताल।

शिक्षा अनुभाग-7 (उच्च शिक्षा)

देहरादून दिनांक 04 फरवरी 2010

विषय:- जनजाति क्षेत्र उप योजना के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिये राजस्व पक्ष में धनराशि स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या डिग्री बजट/8926/2009-10 दिनांक 3-11-09 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनजाति क्षेत्र उप योजना के अर्न्तगत राज्य के जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में संलग्न सूची अनुसार राजकीय महाविद्यालयों में निम्नांकित मदों में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2009-10 में रु0 14.00.लाख (रु0 चौदह लाख मात्र) को व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0	शीर्षक	स्वीकृत धनराशि(हजार रु0 में)
1	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	400
2	26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	600
3	42-अन्य व्यय	400
	योग:-	1400

(रु0 चौदह लाख मात्र)

2. स्वीकृत धनराशि को जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में स्थित राजकीय महाविद्यालयों के अतिरिक्त किसी अन्य महाविद्यालय पर व्यय नहीं किया जायेगा एवं अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति की प्रत्याशा में कोई व्यय नहीं किया जायेगा। तथा समय-समय पर निर्गत वित्तीय एवं मित्तव्ययता सम्बन्धी नियमों एवं दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय केवल स्वीकृत योजनाओं पर ही नियोजन विभाग द्वारा आवंटित परिव्यय की सीमा के अन्तर्गत ही किये जाने का दायित्व विभाग का होगा और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग चालू वर्ष की नई मदों के क्रियान्वयन हेतु नहीं किया जायेगा, धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों/शासनादेशों के तहत निम्नांकित शर्तों के अधीन किया जायेगा:-

- (1) योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहाँ आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
- (2) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसी मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुवल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।
- (3) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।
- (4) आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाये। इसी प्रकार व्यय के सम्बन्ध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन को निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जाये।
- (5) मित्तव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।



(6) व्यय सम्बन्धी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उनमें लेखाशीर्षक के साथ-साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाये।

(7) फर्नीचर, उपकरण एवं कम्प्यूटर आदि का क्रय प्रक्योरमेंट रुल्स 2008, उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों, स्टोर पर्चेज नियमों एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुये नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) स्वीकृत धनराशि के आहरण के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-205(1)/XXVII(1)/2009 दिनांक 25 मार्च, 2009 में उल्लिखित दिशा- निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(9) विभिन्न सम्बन्धित उपकरण आदि का क्रय सम्बन्धित महाविद्यालयों में पूर्व में अनुपलब्धता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित करते हुये यथा आवश्यकतानुसार ही क्रय किया जाय।

(10) उक्त धनराशि का आवंटन महाविद्यालयों को किये जाने से पूर्व, महाविद्यालयों में पूर्व में उपलब्ध फर्नीचर/उपकरण/मशीन संयंत्र आदि के विवरण के क्रम में वर्तमान में वांछित उपकरण ही क्रय किये जाय।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009-2010 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक- 2202- सामान्य शिक्षा-03- विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-796-जनजाति क्षेत्र उप योजना-03-राजकीय महाविद्यालयों का सुदृढीकरण के अधीन उपरोक्त प्रस्तर-2 के व्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 580 (p)/xxvii(3)/2009 दिनांक 20-1-2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीया,

(राधिका झा)

अपर सचिव

सं० 185(1)/xxiv(7) 42(2)/2008 तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।

2- लेखाधिकारी, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी (नैनीताल)।

3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, हल्द्वानी (नैनीताल)।

4- निदेशक एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड।

5- बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन सचिवालय देहरादून।

6- वित्त अनु0-3/नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।

7- विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(.वेदी राम)

अनु सचिव

शासनादेश संख्या 185 / xxiv (7) 42(2)/2008 दिनांक 4/2/2010 का संलग्नक
(धनराशि हजार रुपये में)

कस	महाविद्यालय का नाम	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	26 मशीन साज सज्जा उपकरण	42-अन्य व्यय	योग
1	2	3	4	5	6
1	राजकीय महाविद्यालय मुनस्यारी	40	50	40	130
2	राजकीय महाविद्यालय बलुवाकोट	60	70	60	190
3	राजकीय महाविद्यालय खटीमा	130	200	120	450
4	राजकीय महाविद्यालय जोशीमठ	40	50	40	130
5	राजकीय महाविद्यालय चकराता	—	50	25	75
6	राजकीय महाविद्यालय डाकपत्थर	90	130	75	295
7	राजकीय महाविद्यालय त्यूनी	40	50	40	130
	कुल योग	400	600	400	1400

(रुपया चोदह लाख मात्र)

(विवी शर्मा)

अनु सचिव